# राजस्थान समसामयिकी जुलाई, 2024

संजीव वेबसाइट से नि:शुल्क डाउनलोड करें
राजस्थान, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिकी ( प्रत्येक माह )
साथ ही संजीव वेबसाइट से आप E-Book भी खरीद सकते हैं।
visit us at : www.sanjivprakashan.com

# राजस्थान समसामयिकी जुलाई, 2024
# (Current News from Daily Newspapers)

## Newspaper of 1 July, 2024

### ■ मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तीन अभियानों का शुभारम्भ किया–

30 जून, 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तीन अभियानों का शुभारम्भ किया। ये निम्न है–

(1) राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान
(2) स्टॉप डायरिया अभियान–2024
(3) आभा आईडी बनाओ अभियान (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत)

### ■ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 72 हजार करोड़ रुपए की पार्वती-कालीसिंध-चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना पर एमओयू हुआ–

30 जून, 2024 को मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 72 हजार करोड़ रुपए की पार्वती-कालीसिंध-चंबल अन्तरराज्यीय नदी लिंक परियोजना पर एमओयू हुआ।

**पार्वती-कालीसिंध-चंबल अन्तरराज्यीय नदी लिंक परियोजना**–72 हजार करोड़ रुपए की है। मप्र 35 हजार करोड़ और राजस्थान 37 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगा। मप्र की 3.37 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी और 30 लाख किसान और उनके परिवारों को फायदा होगा। राजस्थान 2.80 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेगा और 2 लाख से अधिक किसान व उनके परिवारों को फायदा होगा। दोनों ओर के 13-13 जिले लाभान्वित होंगे। परियोजना में 17 बांधों का निर्माण होगा, जिनकी जल भराव क्षमता 1477.62 मिलियन घन मीटर होगी।

### ■ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारम्भ हुआ–

30 जून, 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोंक की कृषि उपज मंडी में 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' का राज्यस्तरीय शुभारम्भ किया। इस योजना में राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 6 हजार रुपए की राशि के साथ ही, 2 हजार रुपए अतिरिक्त दिए जाऐंगे। इसके तहत राज्य सरकार ने एक हजार रुपए की पहली किस्त के तौर पर 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 653 करोड़ रुपए भेजे।

## Newspaper of 2 July, 2024

### ■ राजस्थान की 8 सहकारी समितियों को उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार मिला–

**सर्वश्रेष्ठ पैक्स**

- **क्षेत्रीय उत्कृष्टता :** पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीकर।
- **क्षेत्रीय श्रेष्ठता :** 24 एपीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति, अनूपगढ़।

**सर्वश्रेष्ठ केवीएसएस**

- **क्षेत्रीय उत्कृष्टता :** बांसवाड़ा क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बांसवाड़ा।
- **क्षेत्रीय श्रेष्ठता :** कोटपूतली क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. कोटपूतली।

**सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति**

- **क्षेत्रीय उत्कृष्टता :** आपणी सहकारी सेवा समिति लि., माधोराजपुरा।
- **क्षेत्रीय श्रेष्ठता :** केलू महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि., अजमेर

**सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक**

- **क्षेत्रीय उत्कृष्टता :** सराधना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड।
- **क्षेत्रीय श्रेष्ठता :** जेठाना दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति।

### ■ महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और पहल 'ए-हेल्प' योजना शुरू हुई–

हाल ही में पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ए-हेल्प योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की संयुक्त पहल है। उत्तर भारत में इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश है। वर्तमान में यह योजना देश के 11 राज्यों में संचालित है।

इस योजना के माध्यम से जुड़ने पर सखियों के एकजुटता से पशुपालकों से जुड़ने पर न केवल पशुधन उत्पादों में वृद्धि होगी, बल्कि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। पशु सखियों के माध्यम से पशुपालकों को नवीनतम

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

तकनीकों की जानकारी मिलेगी और उसके उपयोग से वे अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना पाएंगे। साथ ही पशु सखियां प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने क्षेत्र में स्वयं को और ज्यादा सक्षम बन पाएंगी।

हेल्प एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसके जरिए पशुपालकों को उनके दरवाजे पर ही पशु सखी के माध्यम से पशुपालन संबंधी सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो सकेंगी। राजस्थान में 9000 पशु सखियों के प्रशिखण का लक्ष्य रखा गया है। इसका अर्थ है लगभग प्रत्येक ग्राम पंचायत पर पशुपालकों की सहायता के लिए एक पशु सखी उपलब्ध होगी।

## Newspaper of 3 July, 2024

### ■ राज्य में नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी मिली–

राजस्थान में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति, 2024 को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी प्रदान दी है।

- यह नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रख-रखाव सेवाओं को बढ़ाने और एयरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केन्द्रित है।
- इसके तहत किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे और कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा।
- साथ ही जयपुर में एयरोसिटी बनाई जाएगी, जिसमें होटल, रेस्त्रां सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।
- प्रदेश के विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधा प्रारंभ की जाएगी।
- प्रदेश की पुरानी हवाई पट्टियों को मरम्मत कर पुन: उड़ान योग्य बनाया जाएगा।

### ■ राज्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की अनूठी पहल के तहत दुकान तक जाने में असमर्थ लोगों को अब घर पर ही राशन मिलेगा–

राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की अनूठी पहल के तहत अब खाद्य सुरक्षा योजना में पंजीकृत ऐसे लोगों को घर पर ही राशन मिलेगा, जो दुकान तक जाने में असमर्थ है।

- इस योजना में ऐसे परिवारों को घर पर ही राशन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के अथवा नि:शक्त है।
- राज्य बजट घोषणा के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में यह योजना शुरू की गई है।
- उचित मूल्य दुकानदार या उसके द्वारा नामित व्यक्ति घर बैठे राशन उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति वितरण के दौरान पोस मशीन, वेट मशीन तथा अन्य आवश्यक सामान साथ लेकर जाएगा।
- दुकानदार को एक से दो राशनकार्ड पर 80 रुपये, तीन से पाँच पर 200 रुपये, छ: से दस पर 300 रुपये, दस से अधिक पर 320 रुपये कमीशन दिया जाएगा।

### ■ 'सशक्त बारां' अभियान का शुभारंभ किया गया–

बारां जिला प्रशासन द्वारा 'सशक्त बारां-प्रगति को शक्ति' अभियान शुरू किया गया है।

**सशक्त बारां अभियान के उद्देश्य–**

- **पर्यावरण** : हरियाला म्हारा बारां अभियान के तहत प्रकृति के संरक्षण के लिए जिले भर में 18 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **स्वास्थ्य** : एनिमिया स्क्रीनिंग, मेंस्ट्रूअल हेल्थ के प्रति व्यापक जन-जागरूकता आदि के लिए व्यापक अभियान चलाए जाएंगे।
- **शिक्षा** : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 'पढ़ेगी म्हारी लाडो' अभियान से अधिकतम बालिका नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। 'पढ़ेगा बारां, बढ़ेगा बारां' अभियान के तहत रेमेडियल कक्षाएँ संचालित करना तथा मेधावी छात्रों के लिए आईआईटी कोचिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

## Newspaper of 4 July, 2024

### ■ न्यायाधीश श्रीचन्द्रशेखर राजस्थान हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने–

3 जुलाई, 2024 को झारखंड हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्रीचन्द्रशेखर को राजस्थान हाइकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर लगाया गया है, अब राजस्थान हाइकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 33 न्यायाधीश हो जाएँगे।

### ■ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पेपर लीक रोकने के लिए नवाचार करेगा; कम्प्यूटर स्क्रीन पर आएगा पेपर तथा जवाब ऑफलाइन ओएमआर शीट पर देना होगा–

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षाओं में पेपरलीक को रोकने के लिए तकनीक का सहारा लेगा। बोर्ड की भर्तियों में अब पेपर हॉर्ड कॉपी में न देकर कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिया जाएगा। यानी परीक्षाएँ सीबीटी मोड पर होंगी। लेकिन जवाब ऑफलाइन ओएमआर शीट पर ही देना होगा। इस नए प्रयोग के साथ 30 अगस्त को पहली परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको लेकर अभ्यर्थियों को गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। परीक्षा समाप्ति पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही परीक्षा केन्द्र

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

छोड़ना होगा। परीक्षा से एक घंटे पहले केन्द्र पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।

**ये भी नियम–**

- कैलेंडर में एग्जाम का मोड अंकित होगा।
- अभ्यर्थियों को अलग से प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।
- अभ्यर्थियों को दो घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पहुँचना होगा।
- आधे घंटे ट्रायल होगा।
- परीक्षा केन्द्र एक घंटे पहले बंद हो जाएगा।

**तो अभ्यर्थी माना जाएगा अयोग्य**–अब नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट में उत्तर देते समय सही जवाब का गोला गहरा करना होगा। अगर कोई उत्तर नहीं दिया तो पांचवां विकल्प गहरा करना होगा। अगर पांचवां विकल्प गहरा नहीं किया तो एक तिहाई नंबर कटेगा। वहीं 10 फीसदी से अधिक प्रश्नों के जवाब गहरे नहीं किए तो अभ्यर्थियों को अयोग्य माना जाएगा।

## ■ राजस्थान देश का पहला राज्य जहाँ सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्ष का एक्शन प्लान तैयार होगा–

राजस्थान में सड़क सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगमी 10 वर्षों का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।

आमजन को इस प्लान के तहत सड़क सुरक्षा के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसका लक्ष्य प्रदेश में वर्ष 2030 तक सड़क हादसों में लगभग 50% की कमी लाना रखा गया है। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता से विभिन्न देशों में सड़क सुरक्षा को लेकर अपनाई जा रही सर्वश्रेष्ठ गतिविधियों को समयोजित कर राज्य सड़क सुरक्षा नीति एवं कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

इसका क्रियान्वयन तीन चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण वर्ष 2025 से 2027, द्वितीय चरण वर्ष 2027 से 2030 और तृतीय चरण वर्ष 2030 से 2033 के मध्य संचालित किया जाएगा। इसके बाद इस कार्ययोजना की समीक्षा की जाएगी।

**Newspaper of 5 July, 2024**

## ■ कृषि विभाग का 'एक व्यक्ति एक पेड़' अभियान के तहत राज्य में एक लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे–

राज्य में पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए हरियाली व पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए हरित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए कृषि विभाग लगभग एक लाख पाँच हजार छायादार और फलदार पौधे लगाने जा रहा है।

'एक व्यक्ति एक पेड़' या 'एक परिवार एक पेड़' अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा समस्त जिलों में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय परिसर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर पौधे लगाये जायेंगे। इस अभियान को पूरे राज्य में आमजन की भागीदारी से सफल बनाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

**ये पौधे लगाए जाएंगे**–अभियान के लिए फलदार और छायादार पौधों का चयन किया गया है। इसमें आम, अमरूद, आंवला, बील, जामुन, सीताफल, इमली, चीकू, शहतूत, मौसमी, नाशपती जैसे फलदार एवं नीम, पीपल, बरगद, गूलर, शीशम, बबूल, सहजन, खेजड़ी एवं रोहिड़ा शामिल है।

**4 साल होगी देखभाल**–पौधोरोपण के बाद उसका 4 वर्ष तक देखभाल एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी विभाग द्वारा की जायेगी। लगाये गये पौधों की वृद्धि की भी नियमित समीक्षा की जाएगी।

## ■ मोहनलाल लाठर मुख्य सूचना आयुक्त बने–

सुरेश चंद गुप्ता, महेन्द्र कुमार पारेख और टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त बनाया गया।

5 जुलाई, 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में मोहन लाल लाठर को नियुक्ति प्रदान की है। राज्यपाल ने इसके साथ ही सुरेश चंद गुप्ता, महेन्द्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त पदों के अंतर्गत इनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिए की है।

**Newspaper of 7 July, 2024**

## ■ नए क्रिमिनल लॉज के तहत राजस्थान में ई-साक्ष्य एप लॉन्च हुए–

देश में एक जुलाई, 2024 से लागू नवीन आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्यों को एप के माध्यम से संकलित कर उन्हें क्लाउड पर स्टोरेज करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा नई शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के द्वारा 'ई-साक्ष्य एप' तैयार किया है, जिसे 5 जुलाई, 2024 को पूरे प्रदेश के लिए लॉन्च कर दिया गया है।

**इस प्रकार करेगा काम**–इस एप को अनुसंधान अधिकारी (आईओ) अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके घटना से संबंधित साक्ष्यों को डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकेंगे। सभी प्रकार के सर्च एवं सीजर की वीडियोग्राफी भी इस एप से की जाएगी। वीडियोज की 'हैस वेल्यू' तत्समय ही निकाली जाएगी एवं न्यायालय में पहुँचने तक इसे सुरक्षित रखा जाएगा।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

**साक्ष्यों से छेड़खानी नहीं हो सकेगी**–वहीं, इस एप पर संकलित साक्ष्यों को सीधे 'क्लाउड' पर डाल दिया जाएगा। ऐसे में क्लाउड पर सुरक्षित डिजिटल साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकेगी और पारदर्शी तरीके से अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त होगा।

**Newspaper of 9 July, 2024**

■ **नीति आयोग द्वारा 'सम्पूर्णता अभियान' शुरू किया गया–**

नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से देशभर में 'संपूर्णता अभियान' शुरू किया गया है।

- यह अभियान आंकाक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) में चयनित देश के 112 जिलों और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) में चयनित 329 जिलों के 500 ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है।
- इस अभियान के माध्यम से 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।
- राजस्थान के 5 जिले एडीपी और 27 ब्लॉक एबीपी में शामिल है। यहाँ संपूर्णता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है।
- सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता अर्जित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- यह अभियान 30 सितम्बर, 2024 तक चलेगा।

**Newspaper of 11 July, 2024**

■ **उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य विधानसभा में परिवर्तित बजट 2024-25 प्रस्तुत किया–**

10 जुलाई, 2024 को उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राज्य विधानसभा में परिवर्तित बजट 2024-25 प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को कई सौगातें दीं। हर वर्ग के साथ ही युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएँ की गईं।

**भविष्य विकसित राजस्थान @2047....10 संकल्प–**

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखंड–'विकसित राजस्थान @2047' के तहत 5 वर्षों की कार्ययोजना बनाकर 'सर्वजन हिताय' आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। भविष्य के लिए हमारे दस संकल्प हैं–

- 350 बिलियन डॉलर इकॉनमी बनाना।
- बुनियादी सुविधाओं–पानी, बिजली और सड़क का विकास।
- सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास।
- सम्मान रहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तीकरण।
- बड़े उद्योगों के साथ–साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन।
- 'विरासत भी और विकास भी' की सोच के साथ धरोहर संरक्षण।
- सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण।
- मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य।
- गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन।
- परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन।

**Newspaper of 13 July, 2024**

■ **राज्य की पहली चीता सफारी रावतभाटा–गांधीसागर में बनेगी–**

राज्य सरकार ने हाल ही पेश किए बजट में गांधीसागर अभयारण्य, भैसरोडगढ़ अभयारण्य और चंबल सेंचुरी को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीता विचरण कॉरिडोर और सफारी के लिए मध्यप्रदेश से एमओयू करते हुए फिसबिलिट स्टडी का प्रावधान किया है। रावतभाटा–गांधीसागर अभयारण्य देश का दूसरा और प्रदेश का पहला चीता सफारी केन्द्र बन जाएगा। चीता सफारी बनाने की यह पहल इसलिए की गई ताकि वहाँ पर्यटन से जुड़ी गतिविधियाँ शुरू हो सके। शुरुआत में अफ्रीका से करीब 5 से 8 चीते लाया जाना प्रस्तावित है। बारिश के बाद सर्दी में चीतों को अफ्रीका से यहाँ लाया जाएगा। भोजन की व्यवस्था के लिए वर्तमान में प्रति वर्गकिमी 15 शाकाहारी वन्य प्राणी उपलब्ध है। जबकि इनके लिए प्रति वर्ग किमी 20 वन्य प्राणियों की जरूरत होगी।

मध्यप्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो में 17 सितंबर, 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। इसके बाद 18 फरवरी, 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते लाए गए। इनमें से 7 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 13 वयस्क चीते कूनो में हैं। गांधी सागर में पहले चरण में दक्षिण अफ्रीका से 5-8 चीते लाए जाएंगे।

**Newspaper of 19 July, 2024**

■ **बीकानेर में 5 करोड़ वर्ष पुराने कॉकरोच के जीवाश्म व कीटों के लार्वा मिले–**

बीकानेर स्थित कोयला, लिग्नाइट और बजरी खनन की खदानों से करोड़ों साल पुराने जीवाश्म मिल रहे है। जिनका देश–दुनिया से वैज्ञानिक यहाँ आकर इन जीवाश्मों का संकलन कर रिसर्च भी कर रहे है। इससे साफ हो रहा है कि रेगिस्तानी इलाका करोड़ों वर्ष पहले ऐसा नहीं रहा होगा, जैसा

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

कि आज है। फ्रांस और उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक यहाँ खदानों से मिले सवा पाँच करोड़ वर्ष पुराने कॉकरोच के जीवाश्य व कीटों के लार्व पर रिसर्च कर चुके है। इसके आधार पर उन्होंने इस क्षेत्र में कभी दलदली भूमि और घना जंगल होने का निष्कर्ष निकाला।

**Newspaper of 25 July, 2024**

■ **मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन होगा; 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया–**

**गोवंश के लिए आवारा शब्द का प्रयोग नहीं होगा, निराश्रित लिखा जाएगा।**

27 जुलाई, 2024 को पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (मांग संख्या-47) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में 250 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना की अनुदान राशि को बढ़ाकर 75% किया जाएगा।

- इस दौरान उन्होंने पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा।
- 500 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाएंगे। साथ ही, 100 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय, 50 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय तथा 25 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को पॉली क्लिनिक में क्रमोन्नत किया जाएगा।
- पशु परिचर के 5,934 पदों के लिए जनवरी, 2024 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।
- सदन ने चर्चा के बाद पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की 15 अरब 58 करोड़ 15 लाख 40 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।

**Newspaper of 26 July, 2024**

■ **राजस्थान की 586 ग्राम पंचायते टीबी मुक्त घोषित की गई–**

हाल ही में भारत सरकार के केन्द्रीय क्षय अनुभाग ने राज्य की 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है। चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी रोगियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएँ एवं योजनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए यह सफलता प्राप्त की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मार्च, 2023 को वाराणसी में आयोजित 'विश्व टीबी रोग दिवस' समारोह में 'टीबी मुक्त पंचायत' अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान का उद्देश्य पंचायतीराज सदस्यों को टीबी रोग कार्यक्रम, रोगियों की सहायतार्थ संबल प्रदान करना एवं पंचायत को टीबी मुक्त करने की दिशा में सम्मिलित प्रयास करना है।

उल्लेखनीय है कि राज्य को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा वर्ष 2024 में 9,325 ग्राम पंचायतों में यह अभियान आयोजित किया जा रहा है।

**Newspaper of 27 July, 2024**

■ **सेना के अग्निवीरों को राजस्थान में भी आरक्षण दिया जाएगा; पाँच राज्य पूर्व में ही 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर चुके; राजस्थान में सेना के अग्निवीरों को राजस्थान पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती में आरक्षण मिलेगा–**

26 जुलाई, 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणा के तहत अब सेना के अग्निवीरों को राजस्थान पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। इन भर्तियों में कितना प्रतिशत आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा अनुमानत: यह आरक्षण पाँच से दस प्रतिशत तक हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि 26 जुलाई, 2024 को कारगिल विजय दिवस पर पाँच राज्यों की भाजपा सरकारों ने अग्निवीरों को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस सेवा और पीएसी, मध्यप्रदेश में पुलिस और सशस्त्र बल, छत्तीसगढ़ में पुलिस और वनरक्षक भर्ती, ओडिशा में पुलिस भर्ती और उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

■ **नि:शुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा; 76.78 अंकों के साथ अव्वल**

हाल ही में राजस्थान नि:शुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने योजना में अनुमोदित दवाओं की संख्या, उपलब्ध दर संविदा, विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता सहित अन्य मानकों में समग्र रूप से अधिकतम अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अनुसार नि:शुल्क दवा योजना के संचालन को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से यह रैंकिंग जारी की गई है। जून 2024 में राजस्थान ने 76.78 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तेलंगाना 75 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा है।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

■ **विधानसभा में युवा संसद कार्यक्रम हुआ, युवाओं को विधानसभा का अनुभव हुआ–**

27 जुलाई, 2024 को राजस्थान विधानसभा में राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वावधान में युवा संसद का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में 41 विद्यालयों के 181 विद्यार्थियों द्वारा विधायक के रूप में सदन में बैठकर जनहित के प्रश्न पूछे गए एवं उनके द्वारा ही स्पीकर, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष व मंत्री की भूमिका निभाई गई। 20 जयपुर के और 21 राज्य के अन्य जिलों व राज्यों के विद्यालयों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

**Newspaper of 28 July, 2024**

■ **सलूम्बर में 'पहल' योजना नवाचार शुरू हुआ–**

सलूम्बर के जिला कलेक्टर द्वारा हर पात्र व्यक्ति को सरकार की जनकल्याकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की याजनाओं से जोड़ने के लिए नवाचार के रूप में 'पहल कैंप' की शुरुआत की गई है।

पहल कैंप में आमजन का आधार कार्ड, जनआधार, बिजली कनेक्शन, बैंक खाता, पीएम जीवन सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, कैटल शेड योजना, कृषक परिवार, म्यूटेशन, उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना के पात्र, श्रम योगी मानधन योजना, ई-श्रम पंजीकरण, विशेष योग्यजन, रोडवेज पास, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, पालनहार, कन्यादान, विवाह पंजीयन और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने पर जोर रहेगा।

**Newspaper of 29 July, 2024**

■ **राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक और राजस्थान वित्त विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ–**

29 जुलाई, 2024 को राज्य विधानसभा ने राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इससे पहले उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दोनों विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किया।

दोनों विधेयकों पर हुई चर्चा तथा इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वक्तव्य के बाद सदन ने दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 के पारित हो जाने से राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से 50,60,91,15,57,000 रुपये (पाँच लाख छः हजार इक्यानवे करोड़ पाँच लाख सतावन हजार रुपये) की राशि के उपयोग के लिए अधिकृत किया गया।

**Newspaper of 30 July, 2024**

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की–**

- **एनएफएसए के लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेण्डर मिलेगा।**
- **1 सितंबर, 2024 से वेतन विसंगति संबंधी सिफारिशें लागू होंगी।**
- **बार काउंसिल को एक बारीय सहायता के रूप में 7 करोड़, 50 लाख रुपये दिए जाएंगे।**
- **भरतपुर एवं बीकानेर यूआईटी विकास प्राधिकरण बनेंगे।**
- **चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती होगी।**

29 जुलाई, 2024 को मुख्यमंत्री ने राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान गत सरकार में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को लागू करने, पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक में अग्निवीर युवाओं को नियुक्ति का प्रावधान, भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण सहित कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की।

**मुख्यमंत्री द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ–**

- 2 वर्षों मे 1 हजार करोड़ रुपये व्यय कर सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ बनेंगे।
- बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 500 के स्थान पर 1000 ई-बस खरीदी जाएंगी।
- भरतपुर एवं बीकानेर यूआईटी का उन्नयन कर विकास प्राधिकरण का गठन होगा।
- जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त की नियुक्ति होगी।
- द्रव्यवती नदी के विकास के लिए नवीन योजना लाई जाएगी।
- 10 हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों एवं निकटवर्ती गांवों को शामिल करते हुए 100 क्लस्टरों में चरणबद्ध रूप से फेकल स्लज मैनेजमेंट के कार्य होंगे।
- बीसलपुर पेयजल योजना में 540 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल संबंधी 9 कार्य होंगे।
- वाटर टेस्टिंग लैब्स को एनएबीएल से मान्यता दिलाने के लिए 15.50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- दौसा शहर में सीवरेज मास्टर प्लान, सूरजगढ़ (झुंझुनूँ), सांगोद (कोटा) में सीवरेज लाइन के कार्य, चेचट एवं

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

खैराबाद कस्बों में क्षतिग्रस्त नालों की सफाई और पुनर्निर्माण कार्य होंगे।

- एससीआईएल और गेल से एमओयू कर 4,100 मेगावाट क्षमता का सृजन होगा।
- कुसुम परियोजना/हैम मॉडल से 1,000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन होगा।
- ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कैप्टिव पावर उत्पादन की सीमा 100% से बढ़ाकर 200% की जाएगी।
- युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 6% ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये होगी।
- पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा।
- खुशियारा (बारां) एवं पण्डेर (जहाजपुर) शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में आईटी पार्क बनेगा।
- स्किलिंग और अप्रेंटिसशिप के लिए पीएम पेकेज के अंतर्गत प्रदेश के ढाई लाख से अधिक युवाओं को लाभ मिलेगा।
- दस्तावेज सत्यापन विभागीय स्तर पर होगा और विज्ञप्ति उपरांत रिक्तियों की संख्या में 50% की वृद्धि का प्रावधान अब 100 प्रतिशत होगा।
- चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती की जाएंगी।
- इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन होगा।
- कालवाड़, बनीपार्क (जयपुर) सहित 6 कॉलेज, 3 नए कन्या महाविद्यालय, बालाहेड़ा (महवा-दौसा) में कृषि महाविद्यालय, 2 पॉलिटेक्निक और एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेगा।
- आरयूएचएस का उन्नयन करते हुए एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना होगी।
- श्रीगंगानगर एवं मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर मरीजों के लिए लीनियर एक्सलरेटर मशीनें लगेंगी।
- प्रतिवर्ष विजयदान देथा साहित्य उत्सव सहित विभिन्न आस्था केन्द्रों, पेनोरमा एवं बावड़ी संबंधी विकास कार्य होंगे।
- जयपुर-जोधपुर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय खुलेंगे।
- एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि से 2 लाख 50 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल के लिए सिंचाई संबंधी कार्य होंगे।
- 40 करोड़ रुपये से राज किसान साथी प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।
- अग्निवीर युवाओं को पुलिस, आरएसी, जेल प्रेहरी, वन रक्षक में नियुक्ति में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
- 100 सीटर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर बनेगा।
- अजमेर-जयपुर स्थित राजस्व मंडल और कर बोर्ड का एकीकरण होगा।
- डीड राइटर्स की संख्या दोगुनी कर 5 हजार की जाएंगी।
- बार काउंसिल को एक बारीय सहायता के रूप में 7 करोड़, 50 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10% की वृद्धि, 2 हजार दुग्ध संकलन केन्द्र खोलने, पशु चिकित्सा संस्थानों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन, परबतसर (डीडवाना-कुचामन), सेड़वा (चौहटन) एवं भाड़ोती (सवाईमाधोपुर) में कृषि मंडी खोलने तथा 150 बीज बैंकों की स्थापना होगी।
- 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा।
- कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार, वेतन विसंगति संबंधी शेष सिफारिशें 1 सितंबर, 2024 से लागू होंगी।
- राजस्थान कॉन्ट्रेचुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के अंतर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तित किए जाने पर नियुक्ति के लिए 5 वर्ष के अनुभव की निर्धारित पात्रता अवधि में वर्ष 2024-25 में 2 वर्ष की छूट मिलेगी।

□□□

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

# संजीव®

49 वर्षों से आपका विश्वसनीय

## आपकी सफलता में सदैव आपका सहयोगी

# CET

## परीक्षा में निश्चित सफलता हेतु उपलब्ध प्रमुख पुस्तकें

## संजीव प्रकाशन की अन्य उपयोगी पुस्तकें

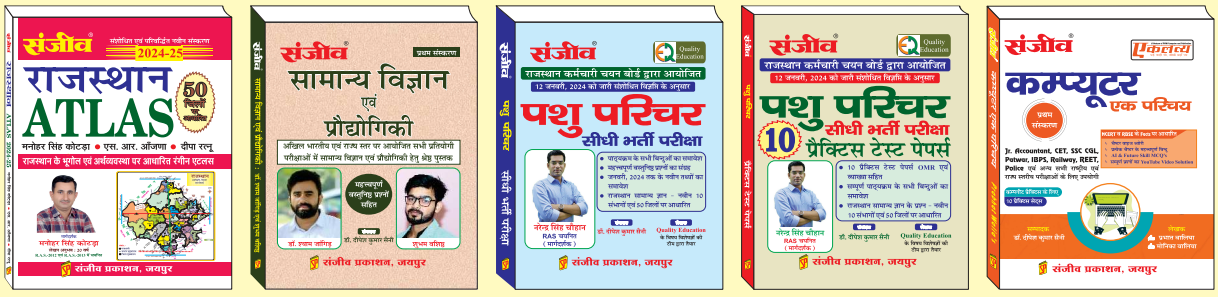


Join Our Telegram

संजीव Telegram चैनल एवं Website से परीक्षा उपयोगी पाठ्य सामग्री निःशुल्क प्राप्त करें। साथ ही संजीव वेबसाइट से आप Books एवं E-Books भी खरीद सकते हैं।


प्रकाशक–संजीव प्रकाशन, जयपुर

Visit us at : www.sanjivprakashan.com